स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का वितरण

3245. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के वितरण में गिरावट आ रही है, जबकि ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के लिए ऋण का कोई प्रावधान नहीं है जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और गत वर्ष बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या निर्णय किए गए थे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) (क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी लघु उद्यमों की योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले शहरी युवकों से लघु उद्यम स्थापित कराना है । सामान्य श्रेणियों के लाभार्थियों को 4 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं को 5000 रुपए की अधिकतम सीमा तक इकाई लागत की 25 प्रतिशत सबसिडी के रूप में दी जाती है । बैंक द्वारा इकाई लागत का 75 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है । इस योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक निम्नलिखित सबसिडी रिलीज की जा चुकी है :—

(लाख रुपए)

1989–90	3805
1990–91	997
1991–92	2781.70

बैंकों द्वारा सबसिडी की राशि से तीन गुणा ऋण रिलीज किया जाता है ।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अन्तर्गत ग्रामीण युवकों को विभिन्न व्यवसायों और नौकरियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद वे स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार प्राप्त कर सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित ऋण दिए जाते हैं।

(ख) आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य नौकरियों के अवसर बढ़ाना है । ग्रामीण विकास मंत्रालय का परिव्यय पर्याप्त रूप से सातवीं योजना में 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आठवीं योजना में 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में मदद मिलेगी ।

नए विकास खण्ड

3246. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को कौन-कौन से राज्यों से नए विकास खण्डों को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए दूरस्थ और भौगोलिक रूप से दुर्गम खण्डों को दो भागों में बांटकर नए विकास खण्डों का निर्णय करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) शून्य । मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें

3247. **श्री रघूभाई ए० परमार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1990–91